

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 998
27 जून, 2019 को उत्तर के लिए

पीएमएवाई के अंतर्गत लक्ष्य

998. श्री एच. वसंत कुमार :

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य-वार विशेष रूप से तमिलनाडु में शहरी गरीबों के लाभ के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत निर्मित किफायती घरों की कुल संख्या कितनी है;
- (ख) क्या सरकार के पास इस योजना को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) आगामी तीन वर्षों के लिए योजना के तहत तय किए गए नए लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है; और
- (घ) वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई योजना क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (ग) : “वर्ष 2022 तक सबके लिए आवास” के सरकार के विजन के अनुसरण में, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), निम्न आय वर्ग (एलआईजी) और मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) श्रेणियों से संबंधित लोगों की आवास संबंधी आवश्यकताओं के समाधान हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता देने के लिए दिनांक 25.06.2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी) {(पीएमएवाई (यू)) को कार्यान्वित कर रहा है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने आवास की वास्तविक मांग का आकलन करने के लिए मांग संबंधी सर्वेक्षण करवाया है। अब तक मान्य मांग लगभग 100 लाख है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अभी तक प्राप्त परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, कुल 81,03,196 आवास अनुमोदित किए गए हैं, जिनमें से 47,57,987 आवास निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं और 26,07,913 आवास पूरे कर लिए गए हैं/उनका कब्जा ले लिया गया है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से परियोजना प्रस्ताव प्राप्त होने पर मार्च, 2020 तक शेष मांग स्वीकृत कर दी जाएगी ताकि 2022 तक सभी आवासों का निर्माण कार्य उत्तरोत्तर पूरा कर लिया जाए। पीएमएवाई(यू) के अंतर्गत निर्मित आवासों का तमिलनाडु राज्य सहित वर्ष-वार तथा राज्य-वार ब्यौरा अनुलग्नक पर दिया गया है।

(घ) : वर्ष 2022 तक “सबके लिए आवास” के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मंत्रालय ने निम्न उपाय किए हैं:

- i. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से आवास की शेष मांग को शीघ्रतिशीघ्र एवं मार्च,2020 तक मंजूर कराने हेतु अनुरोध किया गया है ।
- ii. मिशन के लिए अतिरिक्त बजटीय संसाधन प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय शहरी आवास कोष (एनयूएचएफ) सृजित किया गया है ।
- iii. मंत्रालय ने आवासों की शीघ्र सुपुर्दगी के लिए चुनौती प्रक्रिया के माध्यम से विश्वव्यापी स्तर पर वैकल्पिक तथा नवीनतम प्रौद्योगिकियों की पहचान करने एवं उन्हें सूचीबद्ध करने हेतु वैश्विक आवास प्रौद्योगिकी चुनौती-भारत (जीएचटीसी-इंडिया) आयोजित की।
- iv. मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, शहरी स्थानीय निकायों तथा लाभार्थियों के मध्य एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा प्रोत्साहित करने के लिए कार्यान्वयन एवं नवीनीकरण हेतु “पीएमएवाई(यू) पुरस्कार” आरंभ किए हैं।
- v. सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में गठित केन्द्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति (सीएसएमसी) नई परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता की मंजूरी हेतु प्रत्येक माह बैठक का आयोजन करती है और मिशन की प्रगति की समीक्षा करती है ।
- vi. मंत्रालय आवधिक समीक्षा बैठकों, वीडियो-कॉन्फ्रेंसों तथा क्षेत्रीय दौरों के माध्यम से मिशन की प्रगति की निगरानी करता है ।

vii. पीएमएवाई(यू)-एमआईएस (प्रबंधन सूचना प्रणाली), भुवन पोर्टल, पीएफएमएस (सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली) और स्वीकृत आवासों की जियो-टैगिंग/जियो फेंसिंग के माध्यम से सूचना/अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग प्रभावी निगरानी हेतु किया जा रहा है।

viii. पारदर्शिता और जवाबदेही हेतु प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) पद्धति के माध्यम से भुगतान करना एवं लाभार्थियों को आधार से जोड़ना सुनिश्चित किया जाता है ।

ix. संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) राज्य सत्र पर मिशन के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करती है ।

दिनांक 27.06.2019 के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 998 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पीएमएवाई(यू) के अंतर्गत विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान निर्मित आवासों का
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्षवार पूरे किए गए आवास		
		2016-17	2017-18	2018-19
1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (यूटी)	-	-	22
2	आंध्र प्रदेश	3,299	29,791	2,63,266
3	अरुणाचल प्रदेश	-	16	1,258
4	असम	66	381	12,601
5	बिहार	12,1	2,100	53,420
6	चंडीगढ़ (यूटी)	4,963	57	154
7	छत्तीसगढ़	3,307	3,561	47,510
8	दादर और नगर हवेली (यूटी)	103	366	1,029
9	दमन और दीव (यूटी)	3	65	291
10	दिल्ली (यूटी)	4,244	2,487	17,579
11	गोवा	10	99	393
12	गुजरात	28,9	48,726	1,82,080
13	हरियाणा	549	2,093	10,497
14	हिमाचल प्रदेश	43	202	1,779
15	जम्मू और कश्मीर	203	179	3,623
16	झारखंड	3,886	26,421	43,557
17	कर्नाटक	11,9	31,087	1,05,038
18	केरल	301	3,801	43,022
19	लक्षद्वीप (यूटी)	-	-	-
20	मध्य प्रदेश	5,316	39,119	2,35,457
21	महाराष्ट्र	13,6	35,112	1,17,281
22	मणिपुर	24	177	1,533
23	मेघालय	248	27	375
24	मिजोरम	118	188	626
25	नगालैंड	494	89	1,392
26	ओडिशा	2,771	2,376	48,417
27	पुदुचेरी (यूटी)	79	51	1,414
28	पंजाब	338	1,860	9,407
29	राजस्थान	4,256	8,204	21,641

30	सिक्किम	1	2	31
31	तमिलनाडु	6,636	34,157	1,57,033
32	तेलंगाना	2,792	3,140	43,270
33	त्रिपुरा	161	7,303	32,104
34	उत्तर प्रदेश	9,639	12,005	2,66,262
35	उत्तराखंड	1,479	1,986	5,728
36	पश्चिम बंगाल	7,191	30,765	87,531
	कुल	1,29,1	3,27,993	18,16,621